

**Bill No.5 of 2009**

**THE NATIONAL LAW SCHOOL OF DELHI UNIVERSITY  
(AMENDMENT) BILL, 2009 (BILL NO. 5 OF 2009)**



**(As passed by the Legislative Assembly of National Capital Territory  
of Delhi on 23.6.2009)**

THE NATIONAL LAW SCHOOL OF DELHI UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2009

A

BILL

to amend the National Law School of Delhi University Act, 2007 (Delhi Act 1 of 2008).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows: -

1. **Short title and commencement.** - (1) This Act may be called the National Law School of Delhi University (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of the long title.** - In the National Law School of Delhi University Act, 2007 (Delhi Act 1 of 2008) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in the long title, for the words "School of Delhi University Act", occurring after the word "Law" and before the figures "2007", the words "University, Delhi Act," shall be substituted.

3. **Amendment of section 1.** - In the principal Act, in section 1, in sub-section (1), for the words "School of Delhi University Act", occurring after the word "Law" and before the figures "2007", the words "University, Delhi Act," shall be substituted.

4. **Amendment of section 2.** - In the principal Act, in section 2, for clause (12), the following clause shall be substituted, namely: -

"(12) "University" means the National Law University, Delhi established under section 3 of this Act;"

5. **Amendment of section 3.** - In the principal Act, in section 3, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) There shall be established in the National Capital Territory of Delhi a University by the name of "the National Law University, Delhi."



**6. Amendment of section 9.** – In the principal Act, in section 9, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(2) The term of the Vice-Chancellor shall be for a period of five years.”

**7. Amendment of section 13.** – In the principal Act, in section 13 –

(a) in sub-section (1), clause (a) shall be omitted and the remaining clauses shall be re-numbered as clauses (a) to (h) respectively.”;

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Executive Council.”.

**8. Amendment of section 14.** – In the principal Act, in section 14, for sub-section (8), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(8) Every meeting of the Executive Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen by the members present.”.

**9. Amendment of section 20.** – In the principal Act, in section 20, in sub-section (4), for the words “three years”, the words “five years” shall be substituted.

**10. Amendment of section 21.** – In the principal Act, in section 21 –

(a) in sub-section (1), after the word “person”, occurring after the word “academic” and before the words “not below”, the words “in law” shall be inserted;

(b) after sub-section(2), the following sub-section shall be inserted, namely:-



“(3) The term of appointment of the Registrar shall be for a period of five years or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and he shall be eligible for re-appointment by the Vice-Chancellor with the approval of the Chancellor.”.

**11. Substitution of new section for section 26.** – In the principal Act, for section 26, the following section shall be substituted, namely:-

**“26. Appointment of first Vice-Chancellor and first Registrar.-**

Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes, the first Vice-Chancellor who shall be an academic person in law or an eminent jurist, shall be appointed by the Chancellor and shall hold office of the Vice-Chancellor for a period of five years and the person so appointed shall be eligible for grant of extension in tenure by the Chancellor. The first Registrar who shall be an academic person in law and of the rank of not less than a professor shall be appointed by the Chancellor on the recommendations of the Vice-Chancellor. The said officer shall hold office for a period of five years or till a regular Registrar is appointed, whichever is earlier.”

---

This Bill has been passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 23<sup>rd</sup> day of June, 2009.

Delhi  
Dated 23<sup>rd</sup> June, 2009.



  
(Dr. Yoganand Shastri)

Speaker  
Legislative Assembly of the National  
Capital Territory of Delhi



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]  
No. 92]

दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2009/आषाढ़ 1, 1931  
DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2009/ASADHA 1, 1931

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 72  
[N.C.T.D. No. 72

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जून, 2009

सं. फा. 21(5)/09/एल.ए.एस. IV/विधायी/4355.—  
सर्वसाधारण सूचनार्थ हेतु प्रकाशित किया जाता है:—

राष्ट्रीय विधि विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन)  
विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्या 05)

जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में  
दिनांक 22 जून, 2009 को पुरःस्थापित किया गया।

राष्ट्रीय विधि विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007  
(2008 का दिल्ली अधिनियम 1) में संशोधन के लिये

एक

विधेयक

इसे भारतीय गणराज्य के साठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  
दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाये:—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :—(1) इसे राष्ट्रीय विधि  
विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 कहा  
जाये।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. विस्तृत शीर्षक का संशोधन :—राष्ट्रीय विधि विद्यालय,  
दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम 1)  
(यहाँ बाद में “मूल अधिनियम” के रूप में संदर्भित) के विस्तृत  
शीर्षक में “विधि” शब्द के पश्चात् तथा “2007” अंकों से पूर्व आने  
वाले दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यालय अधिनियम शब्दों के स्थान पर  
“विश्वविद्यालय, दिल्ली अधिनियम” शब्दों को प्रतिस्थापित किया  
जाएगा।

3. धारा 1 का संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 1 की  
उप-धारा (1) में “विधि” शब्द के पश्चात् तथा “2007” अंकों से  
पूर्व आने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यालय अधिनियम, शब्दों  
के स्थान पर “विश्वविद्यालय, दिल्ली अधिनियम” शब्दों को प्रतिस्थापित  
किया जाएगा।

4. धारा 2 का संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 2 के  
खंड (12) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया  
जाएगा, अर्थात् —

“(12) “विश्वविद्यालय” का अर्थ है इस अधिनियम की  
धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली”।

5. धारा 3 का संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 3 की  
उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की  
जाएगी, अर्थात् :—



“(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में “राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली” नामक दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी”।

6. धारा 9 का संशोधन.—मूल अधिनियम धारा 9 में उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(2) कुलपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा”।

7. धारा 13 का संशोधन.—मूल अधिनियम धारा 13 में—

(क) उप-धारा (1) के खण्ड (क) को हटाया जाएगा तथा शेष खण्डों को (क) से (ज) तक क्रमशः पुनः संख्याकित किया जाएगा”;

(ख) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(2) कुलपति कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष होगा”।

8. धारा 14 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 14 में उप-धारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(8) कार्यकारी परिषद की प्रत्येक बैठक की कुलपति द्वारा अध्यक्षता की जाएगी तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी”।

9. धारा 20 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) में “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पाँच वर्ष” शब्दों को प्रतिस्थापित की जाएगी।

10. धारा 21 का संशोधन.—मुख्य अधिनियम की धारा 21 में—

(क) उप-धारा (1) में “अकादमिक” शब्द के पश्चात् तथा “कम नहीं” शब्दों से पहले आने वाले शब्द “व्यक्ति” के पश्चात् “विधि में” शब्दों को सन्निविष्ट किया जाएगा;

(ख) उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

“(3) कुल सचिव की नियुक्ति अवधि पाँच वर्ष के लिए अथवा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने, इनमें जो भी पहले हो, तक होगी तथा वह कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति द्वारा पुनः नियुक्ति का पात्र भी होगा।”

11. धारा 26 के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम में धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“26 प्रथम कुलपति तथा प्रथम कुल सचिव की नियुक्ति.— इस अधिनियम या संविधियों में कुछ भी रहते हुए प्रथम कुलपति जो विधि का शिक्षाविद् व्यक्ति या प्रतिष्ठित न्यायविद् होगा तथा उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की

जाएगी तथा कुलपति के पद पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा ऐसी नियुक्ति वाले व्यक्ति की सेवा कुलाधिपति द्वारा आगे बढ़ाई जा सकती है। प्रथम कुल-सचिव जो विधि का शिक्षाविद् व्यक्ति होगा तथा प्रोफेसर से कम पद का नहीं होगा। कुलाधिपति द्वारा कुलपति की सिफारिश से नियुक्त किया जायेगा। उक्त अधिकारी पाँच वर्ष तक या किसी नियमित कुल सचिव के नियुक्त होने तक, इनमें जो भी पहले हो, तक पदासीन रहेगा।”

सिद्धार्थ राव, सचिव

### उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय विधि विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 1) में यह अनुभव किया गया कि संगठन को विश्वविद्यालय के रूप में विशिष्ट स्वरूप प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप धारा 2 (12) तथा धारा 3 में तथा लम्बे शीर्षक में संशोधन के अलावा धारा 1 में भी संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त के अलावा उक्त विश्वविद्यालय की नियामक परिषद् ने 13 अगस्त, 2008 को माननीय उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायमूर्ति तथा उक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की अध्यक्षता में दिनांक 13 अगस्त, 2008 की बैठक में उक्त अधिनियम की विभिन्न अन्य धाराओं में संशोधन का सुझाव दिया है। नियामक परिषद् द्वारा बताए गए सुझाव धारा 1, 3, 9, 13, 14, 21 तथा 26 से संबंधित हैं। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से विधि के कुछ प्रासंगिक प्रावधानों को और आगे सुदृढ़ करने तथा दिल्ली सरकार के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धति में एकरूपता बनाए रखने तथा कुछ व्यावहारिक क्रियान्वयन पक्षों को मजबूत बनाना है।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

### वित्तीय ज्ञापन

राष्ट्रीय विधि विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 में निहित प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से मूल व्यय द्वारा केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता अपेक्षित नहीं होगी।

### प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ज्ञापन

राष्ट्रीय विधि विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 किसी अधीनस्थ कार्यप्रणाली को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान नहीं करता।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

### NOTIFICATION

Delhi, the 22nd June, 2009

F. No. 21(5)/2009/LAS-IV/Leg/4355.—The following is Published for general Information :—



**THE NATIONAL LAW SCHOOL OF DELHI  
UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2009  
(BILL NO. 5 OF 2009)**

(As introduced in the Legislative Assembly of National  
Capital Territory of Delhi on 22-6-2009)

A

BILL

to amend the National Law School of Delhi University Act,  
2007 (Delhi Act 1 of 2008).

BE it enacted by the Legislative Assembly of the  
National Capital Territory of Delhi in the Sixtieth Year of  
the Republic of India as follows :—

**1. Short title and commencement.**—(1) This Act may  
be called the National Law School of Delhi University  
(Amendment) Act, 2009.

(2) It shall come into force on the date of its  
publication in the Delhi Gazette.

**2. Amendment of the long title.**—In the National  
Law School of Delhi University Act, 2007 (Delhi Act 1 of  
2008) (hereinafter referred to as the “principal Act”), in the  
long title, for the words “School of Delhi University Act”,  
occurring after the word “Law” and before the figures  
“2007”, the words “University, Delhi Act,” shall be  
substituted.

**3. Amendment of section 1.**—In the principal Act,  
in section 1, in sub section (1), for the words “School of  
Delhi University Act”, occurring after the word “Law” and  
before the figures “2007”, the words “University, Delhi  
Act,” shall be substituted.

**4. Amendment of section 2.**—In the principal Act, in  
section 2, for clause, (12), the following clause shall be  
substituted, namely :—

“(12) “University” means the National Law  
University, Delhi established under section 3 of this  
Act;”

**5. Amendment of section 3.**—In the principal Act, in  
section 3, for sub-section (1), the following sub-section  
shall be substituted, namely :—

“(1) There shall be established in the National Capital  
Territory of Delhi a University by the name of “the  
National Law University, Delhi.”

**6. Amendment of section 9.**—In the principal Act, in  
section 9, for sub-section (2), the following sub-section  
shall be substituted, namely :—

“(2) The term of the Vice-Chancellor shall be for a  
period of five years.”

**7. Amendment of section 13.**—In the principal Act,  
in section 13—

(a) in sub-section (1), clause (a) shall be omitted  
and the remaining clauses shall be re-numbered  
as clauses (a) to (h) respectively.”;

(b) for sub-section (2), the following sub-section  
shall be substituted, namely :—

“(2) The Vice-Chancellor shall be the Chairman  
of the Executive Council.”.

**8. Amendment of section 14.**—In the principal Act,  
in section 14, for sub-section (8), the following sub-section  
shall be substituted, namely :—

“(8) Every meeting of the Executive Council shall be  
presided over by the Vice-Chancellor and in his  
absence by a member chosen by the members  
present.”.

**9. Amendment of section 20.**—In the principal Act,  
in section 20, in sub-section (4), for the words “three years”,  
the words “five years” shall be substituted.

**10. Amendment of section 21.**—In the principal Act,  
in section 21—

(a) in sub-section (1), after the word “person”,  
occurring after the word “academic” and before  
the words “not below”, the words “in law” shall  
be inserted;

(b) after sub-section (2), the following sub-section  
shall be inserted, namely :—

“(3) The term of appointment of the Registrar  
shall be for a period of five years or till he attains  
the age of sixty-five years, whichever is earlier,  
and he shall be eligible for re-appointment by  
the Vice-Chancellor with the approval of the  
Chancellor.”.

**11. Substitution of new section for section 26.**—In  
the principal Act, for section 26, the following section shall  
be substituted, namely :—

**“26. Appointment of first Vice-Chancellor and first  
Registrar.**—Notwithstanding anything contained in  
this Act and the Statutes, the first Vice Chancellor  
who shall be an academic person in law or an eminent  
jurist, shall be appointed by the Chancellor and shall  
hold office of the Vice Chancellor for a period of five  
years and the person so appointed shall be eligible  
for grant of extension in tenure by the Chancellor.  
The first Registrar who shall be an academic person  
in law and of the rank of not less than a professor  
shall be appointed by the Chancellor on the  
recommendations of the Vice-Chancellor. The said  
officer shall hold office for a period of five years or  
till a regular Registrar is appointed, whichever is  
earlier.”.

SIDDHARATH RAO, Secy.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the National Law School of Delhi University Act,  
2007 (Delhi Act 1 of 2008), it is felt that the name of the  
University needs to be amended to bring out the distinctive  
character of the organization as an University.  
Consequential amendments in section 2(12) and section 3  
will also need to be carried out, besides amendment of the  
long title and that of section 1.

In addition to the above, the Governing Council of the said University in its meeting held on 13th August, 2008 under the Chairmanship of the Hon'ble Chief Justice of Deihl High Court and the Chancellor of the said University has suggested amendments in various other sections of the said Act. These amendments suggested by the Governing Council pertain to sections 1, 3, 9, 13, 14, 21 and 26. The proposed amendments are intended to further strengthen the relevant provisions of the law and certain practical operational aspects and generally to maintain uniformity of systems in universities under the Government of NCT of Delhi.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

### **FINANCIAL MEMORANDUM**

For the implementation of the proposals contained in the National Law School of Delhi University (Amendment) Bill, 2008, no additional financial assistance will be required from the Central Government through substantive expenditure from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi.

### **MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

The National Law School of Delhi University (Amendment) Bill, 2008, does not seek to confer power of legislation on any subordinate functionaries.